

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल फोन 0755-2551486-87 फैक्स 2550094

क्र. | 0/2/MGNREGS-MP/NR-1/14

भोपाल, दिनांक 1/2/2014

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला/जिला पंचायत — (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय:- मानव अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित अशासकीय संगठन एवं अन्य संस्थाओं के सदस्यों को सहयोग देने विषयक।

संदर्भ:— राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को संबोधित पत्र क्र. — LD/MISC/CD-2013 दिनांक 11-12-2013

कृपया संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा लेख किया गया है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित अशासकीय संगठन एवं अन्य संस्थाओं के सदस्यों द्वारा जिलों में भ्रमण के दौरान उन्हें आवश्यक सहयोग नहीं दिया जाता है। इन संगठनों की मदद से मानव अधिकारों की अवहेलना होने से जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अतः संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल, दिनांक / /2_/2014

पृ. क्र. 1013 MGNREGS-MP/NR-1/14 प्रतिलिपि :-

 महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी—ब्लॉक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए — नई दिल्ली की ओर उनके संदर्भित पत्र के पालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सचनार्थ प्रेषित।

 अवर सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 संयुक्त आयुक्त (समन्वय) विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल की ओर नेमीटीप क्र. — 17/22/वि—8/मॉनिट/14 दिनांक 20.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

डॉ. इरविन्दर सोही बिहरिया, आई.आर.एस.

महासचिव

Dr. Parvinder Sohi Behuria, IRS Secretary General



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जीपीओ काम्प्लवन आईएनए. नड़ दिल्ली-110 023 भारत

National Human Rights Commission Manay Adhikar Bhawan, C-Block, GPO Complex. INA New Delhi-110023 India

11th December 2013

6732 17/12/2013

During the visits of the National Human Rights Commission to various States in the country, the NGOs and Human Rights Defenders have drawn the attention of the Commission to the functional environment in the States being not very conducive to their work. They have alleged that functionaries of NGOs and Human Rights Defenders are being threatened and some times have been physically manhandled by the State authorities. It has been stated by them that they live in constant fear of being implicated in false cases. These issues have also been discussed with the State Government officers during the Commission meetings, Open hearings and Camp sittings.

It would, therefore, be of immense help if State Government functionaries are sensitized about the problems being faced by NGOs and Human Rights Defenders. The latter should be treated as partners in bringing about a positive change in the human rights environment in the States.

with regards.

Yours sincerely,

ler Die Bicheri

(Parvinder Sohi Behuria)

Shri Anthony J C Desa Chief Secretary Government of Madhya Pradesh Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004

फोन : 91-11-24663260, फक्स : 91-11-24651329

Phone : 91-011-24663260, Fax : 91-011-24663261, E-mail signfric@nic.in, Website www.nhr.inic.ii.